गांधी स्मारक निधि का मासिक मुखपत्र

संस्थाकुल

अगस्त, 2023 वर्ष – 54 अंक – 5

वार्षिक सहयोग राशि : रु. 20.00
एक प्रति : रु. 2.00
कुल पृष्ठ : 12

दस्तावेज़

स्वतंत्रता और स्वाधीनता की स्थापना के लिए

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त, 1942 को पारित प्रस्ताव

अगस्त क्रान्ति : 1942

कार्य–समिति ने 14 जुलाई, 1942 के अपने प्रस्ताव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आगे जो विषय रखा है कमेटी ने उस पर तथा उसके बाद की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की परिस्थिति का क्रमिक परिवर्तन ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार प्रवक्ताओं के बयान और भारत तथा विदेशों में हुई टीका–टिप्पणियां और आलोचनाएं भी शामिल हैं, बहुत ध्यान से विचार किया है। कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, और उसका समर्थन करती है, और उसकी यह राय है कि बाद की घटनाओं से उसका औचित्य और अधिक सिद्ध हो गया है और यह चीज स्पष्ट हो गई है कि भारत में ब्रिटिश शासन की अविलम्ब समाप्ति भारत और संयुक्त राष्ट्रों के ध्येय की सफलता दोनों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। उस शासन के जारी रहने से भारत की अधोगति हो रही है, वह दुर्बल हो रहा है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व–स्वतंत्रता में योग देने की उनकी क्षमता उत्तरोत्तर कम होती जा रही है।

कमेटी को यह देखर बड़ी निराशा हुई है कि रूसी और चीनी मोर्चो पर स्थिति बिगड़ रही है। रूसी एवं चीनी लोग अपनी स्वाधीनता के रक्षार्थ जो वीरता दिखा रहे हैं, कमेटी उसकी भूरि–भूरि सराहना करती है। यह उत्तरोत्तर बढ़ता संकट उन सभी लोगों को जो स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नीशील हैं और आक्रमणग्रस्त लोगों से सहानुभूति रखते हैं, इस कर्त्तव्य के लिए बाध्य करता है कि वे मित्र–राष्ट्रों द्वारा अभी तक अपनाई गई नीति के मूल सिद्धान्तों की जांच करें, क्योंकि वह नीति बार–बार विनाशकारी रूप से विफल रही है। इस तरह के उद्देश्यों, नीतियों और तरीकों पर जमे रहने से विफलता सफलता में नहीं बदली जा सकेगी, क्योंकि पिछला अनुभव यह दिखाता है कि विफलता के बीज उनके भीतर ही मौजूद हैं। इन नीतियों का आधार स्वतंत्रता की अपेक्षा अधीन और औपनिवेशिक देशों पर अपना आधिपत्य तथा साम्राज्यवादी परम्परा और पद्धति को जारी रखना ही अधिक रहा है। साम्राज्य को कब्जे में रखने से शासक–सत्ता की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है, उलटे वह उसके लिए एक बोझ और अभिशाप बन गया है। भारत जो आधुनिक साम्राज्यवाद की क्लासिक लीला–स्थली है, आज प्रश्न का मूल बिन्दु बन गया है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से ही ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्रों को परखा जायेगा और एशिया एवं अफ्रिका के लोग आशा और उत्साह से भर उठेंगे।

इस प्रकार इस देश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक ऐसा महत्वपूर्ण और तात्कालिक प्रश्न है जिस पर इस युद्ध का भविष्य और स्वतंत्रता तथा जनतंत्र की सफलता निर्भर है। भारत के स्वतंत्र होने से यह सफलता सुनिश्चित हो जायेगी, क्योंकि तब वह अपने सारे के सारे विपुल साधन स्वतंत्रता के लिए तथा नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में झोंक देगा। इससे न केवल युद्ध का पासा पलट जायेगा, बल्कि सभी अधीन

और उत्पीड़ित लोग संयुक्त राष्ट्रों के पक्ष में हो जायेंगे और इन राष्ट्रों को, जिनका सहयोगी भारत होगा, विश्व का नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करेंगे, जबकि पराधीन भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतीक बना रहेगा, और उस साम्राज्यवाद के कलंक का असर सभी संयुक्त राष्ट्रों के भाग्य पर पड़ेगा।

इसलिए आज के संकट की यह आवश्यक मांग है कि भारत स्वाधीन हो और ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त हो। भविष्य में पूरी की जानेवाली किसी भी प्रतिज्ञा या गारंटी से इस स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ सकेगा और न इस संकट का मुकाबला ही किया जा सकेगा। उनसे जन–मानस पर आवश्यक मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ सकता। अभी मिली स्वतन्त्रता ही अपनी ज्योति से करोड़ों लोगों में वह शक्ति और उमंग जमा सकेगी, जिससे युद्ध का नक्शा तुरन्त बदल जायेगा।

अ. भा. कांग्रेस कमेटी इसलिए ब्रिटिश सत्ता को भारत से हटाने की अपनी मांग को पूरे जोर से दोहराती है। भारत की स्वाधीनता की घोषणा के बाद एक अस्थायी सरकार बन जायेगी और स्वतंत्र भारत संयुक्त राष्ट्रों का सहयोगी बन जायेगा तथा स्वतंत्रता–संघर्ष के संयुक्त अभियान के कष्टों और दुःखों में उनका साक्षी होगा। अस्थायी सरकार केवल देश के मुख्य दलों और समुदायों के सहयोग से ही बन सकती है। इस प्रकार वह भारतीय जनता के सभी महत्त्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक मिली–जुली सरकार होगी। उनका मुख्य कार्य भारत की प्रतिरक्षा, मित्र–राष्ट्रों के साथ मिलकर सभी उपलब्ध सैनिक एवं अहिंसक शक्तियों द्वारा आक्रमण का प्रतिरोध तथा खेतों और कारखानों में काम करनेवाले लोगों की खुशहाली और उन्नति को प्रोत्साहन देना होगा चाहिए, क्योंकि समस्त सत्ता और अधिकार तो बुनियादी तौर पर आखिर उन्हीं के होने चाहिए। अस्थायी सरकार एक संविधान सभा की योजना बनायेगी, जो भारत के शासन के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करेगी जो जनता के सभी वर्गों को स्वीकार हो। कांग्रेस की राय में, यह संविधान संघीय होना चाहिए जिसमें संघ की इकाइयों को अधिकतम स्वायत्तता हो और अवशिष्ट अधिकार उन इकाइयों को प्राप्त हों। भारत और मित्र–राष्ट्रों के भावी सम्बन्धों में तालमेल बैठाने का काम इन सभी स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि अपने पारस्परिक लाभ के लिए और आक्रमण के प्रतिरोध के समान कार्य में अपने सहयोग के लिए परस्पर विचार–विमर्श करके करेंगे। स्वतन्त्र हो जाने पर भारत जनता के संयुक्त संकल्प और शक्ति से आक्रमण का प्रभावशाली ढंग से प्रतिरोध कर सकेगा।

भारत की स्वतंत्रता अन्य सभी एशियाई राष्ट्रों की, जो इस समय विदेशी अधिपत्य के अधीन हैं, स्वतंत्रता का प्रतीक और भूमिका होनी चाहिए। बर्मा, मलाया, इंडो–चायना, डच इंडीज, ईरान और ईराक को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यह चीज साफ समझ लेनी चाहिए कि इनमें से ज्यादातर देश जिस तरह अब जापान के नियंत्रण में हैं उसी तरह बाद में किसी अन्य औपनिवेशिक सत्ता के शासन या नियंत्रण में नहीं रखे जाने चाहिए।

संकट की इस घड़ी में अ. भा. कांग्रेस कमेटी को जहां मुख्य चिन्ता भारत की स्वाधीनता और प्रतिरक्षा की है, वहां कमेटी की यह भी राय है कि भावी शान्ति और विश्व की सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रगति के लिए स्वतंत्र राष्ट्रों का एक विश्व–संघ आवश्यक है। आधुनिक जगत की समस्याएं किसी और आधार पर सुलझाई ही नहीं जा सकतीं। इस तरह के विश्व–संघ से उसके अंगीभूत राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो जायेगी, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण और उसका शोषण रुक जायेगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की रक्षा और सभी पिछड़े इलाकों तथा लोगों की प्रगति हो सकेगी, और विश्व के साधनों को सबकी समान भलाई के लिए एकत्रित किया जा सकेगा। इस तरह का विश्व–संघ स्थापित हो जाने पर निरस्त्रीकरण सभी देशों के लिए व्यवहारिक हो जायेगा, राष्ट्रीय थल–सेनाओं, नौसेनाओं और वायु सेनाओं की कोई जरूरत नहीं रहेगी, विश्व–संघ की एक प्रतिरक्षा सेना ही विश्व–शान्ति रखेगी तथा आक्रमण को रोकेगी।

स्वाधीन भारत इस तरह के विश्व–संघ में खुशी से शामिल होगा और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अन्य देशों के साथ बराबरी के आधार पर सहयोग करेगा।

इस तरह के संघ के द्वार उन सभी राष्ट्रों के लिए जो उसके मूल सिद्धान्तों से सहमत हों, खुले होने चाहिए। फिर भी, युद्ध को दृष्टि में रखते हुए यह संघ आरम्भ में अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्रों तक ही सीमित हो। यदि अभी इस तरह का

कदम उठाया गया तो उसका युद्ध पर धुरी–राष्ट्रों के लोगों पर और भावी शान्ति पर बहुत ही जबरदस्त असर पड़ेगा।

परन्तु कमेटी बड़े अफसोस के साथ यह महसूस करती है कि युद्ध की दुःखान्त और अदम्य शिक्षाओं और संसार पर मंडराते खतरों के बावजूद, किसी भी देश की सरकार अभी विश्व–संघ के लिए यह अनिवार्य कदम उठाने को तैयार नहीं है। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियाओं और विदेशी समाचार पत्रों की भ्रान्त आलोचनाओं से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत की स्वाधीनता की स्पष्ट मांग तक का विरोध किया जा रहा है, जबकि यह मांग, मुख्य रूप से मौजूदा खतरे का सामना करने और संकट की इस घड़ी में भारत को अपनी रक्षा तथा चीन और रूस की सहायता कर सकने के योग्य बनाने के लिए ही रखी गई है। कमेटी को इस बात की बड़ी फिक्र है कि चीन और रूस की प्रतिरक्षा में, जिनकी आजादी अमूल्य है और अवश्य कायम रहनी चाहिए, किसी भी तरह बाधा न पड़े और संयुक्त राष्ट्रों की प्रतिरक्षा–क्षमता को कोई क्षति न पहुंचे। परन्तु भारत और इन राष्ट्रों, दोनों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर निष्क्रियता और विदेशी शासन की अधीनता से न केवल भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है और अपनी रक्षा तथा आक्रमण का प्रतिरोध कर सकने की उसकी क्षमता घट रही है, अपितु इस दिन–प्रतिदिन बढ़ते खतरे का कोई प्रतिकार नहीं हो पा रहा है और संयुक्त राष्ट्रों के लोगों की कोई सेवा भी नहीं हो पा रही है। ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्रों के नाम कार्य–समिति की पुरजोर अपील का अभी तक कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला है, और बहुत से विदेशी क्षेत्रों में उसकी जो आलोचना हुई है वह यही दिखाती है कि भारत और विश्व की जरूरतों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। यही नहीं, कभी–कभी तो उसमें भारत की आजादी के प्रति द्वेष तक दिखाई देता है, जो आधिपत्य और जातीय अहम्मन्यता की मनोवृत्ति का द्योतक है। एक गर्वीली जाति, जिसे अपनी शक्ति और अपने ध्येय के औचित्य का एहसास है, इसे कदापि सहन नहीं कर सकती।

अ. भा. कांग्रेस कमेटी, विश्व–स्वतंत्रता के हित के लिए, इस आखिरी घड़ी में ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्रों के नाम अपनी यह अपील फिर से दोहराना चाहेगी। परन्तु कमेटी यह महसूस करती है कि राष्ट्र को उस साम्राज्यवादी और निरंकुश सरकार के विरुद्ध, जो उस पर आधिपत्य जमाये हुए है और उसे अपने तथा मानवता के हित में कार्य करने से रोक रही है, अपने संकल्प को पूरा करने के प्रयत्नों से रोकना अब और उचित नहीं है। कमेटी इसलिए, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के भारत के अनन्य अधिकार की स्थापना के लिए यथासम्भव बड़े से बड़े पैमाने पर एक अहिंसक जन–आन्दोलन छेड़ने की मंजूरी देने का निश्चय करती है, ताकि देश पिछले बाईस सालों के शान्तिपूर्ण संघर्ष में संचित अपनी सम्पूर्ण अहिंसात्मक शक्ति को काम में ला सके। इस तरह के संघर्ष का गांधीजी के नेतृत्व में चलना अनिवार्य है, और कमेटी उनसे जो कदम उठाये जाने हैं उनमें राष्ट्र का नेतृत्व और पथ–प्रदर्शन करने की प्रार्थना करती है।

कमेटी भारत के लोगों से अपील करती है कि वे सामने आने वाले खतरों और कठिनाइयों का साहस और धैर्य से मुकाबला करें, गांधीजी के नेतृत्व में एकजुट हों, और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अनुशासित सैनिकों की हैसियत से उनके आदेशों का पालन करें। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अहिंसा इस आन्दोलन का आधार है। ऐसा मौका आ सकता है कि आदेश जारी करना या आदेशों का हमारे लोगों तक पहुंचना असम्भव हो जाये और कोई भी कांग्रेस कमेटी कार्य न कर सके। ऐसी स्थिति होने पर इस आन्दोलन में भाग लेनेवाले हर नर–नारी को, सामान्य आदेशों की हदबन्दी में से अपने लिए स्वयं काम करना होगा। स्वतंत्रता के इच्छुक और उसके लिए प्रयत्नशील हर भारतीय को अपना मार्ग–दर्शक स्वयं होना चाहिए और उस कठिन मार्ग पर जो अन्त में हमें भारत की स्वाधीनता और मुक्ति तक ले जायेगा, अविश्रान्त आगे बढ़ते रहना चाहिए।

अन्त में अ. भा. कांग्रेस कमेटी स्वतंत्र भारत के भावी शासन के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर चुकने के बाद सभी सम्बन्धित लोगों के आगे यह चीज बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि जन–संघर्ष छेड़ने में उसका इरादा कांग्रेस के लिए सत्ता प्राप्त करना कतई नहीं है। सत्ता जब प्राप्त होगी तो वह भारत की समस्त जनता की होगी।

(अंग्रेजी से)

इंडियन ऐनुअल रजिस्टर, 1942, जिल्द 2, पृ. 209–11 । *हरिजन* 9.8.1842 और *ट्रांसफर ऑफ पॉवर*, जिल्द 2, पृ. 621–24 भी।

(सम्पूर्ण गांधी वांगमय : खण्ड–78, पृष्ठ 509–513)

सरकार ने अंततः सर्व सेवा संघ पर बलात कब्जा कर ही लिया !

सरोज कुमार

महात्मा गांधी की शारीरिक हत्या करने के बाद उनकी वैचारिक हत्या करने की असफल कोशिशों में लम्बे समय से जुटी हिन्दू राष्ट्र की अपनी विचाराधारा की पोषक देश की मौजूदा सरकार ने गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के प्रति अपनी घृणा के नए न्यूनतम स्तर का नमूना पेश किया है। आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से गांधी विचार के प्रचार–प्रसार के लिए 1948 में स्थापित संस्था सर्व सेवा संघ के वाराणसी स्थित परिसर पर जबरन कब्जा कर लिया है।

वाराणसी, जिसे काशी नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन काल से शिक्षा–संस्कृति का केन्द्र रहा है। तमाम महापुरुषों, संतों, सूफियों, विद्वानों और विचारकों ने इसीलिए काशी का भ्रमण किया और अपने विचारों से उस धरती को समृद्ध किया। काशी एक मात्र ऐसी नगरी है जहां हर धर्म, संप्रदाय और संस्कृति का स्वागत और सम्मान हुआ। सभी ने एक साथ मिलकर एक ऐसी समृद्ध संस्कृति की रचना की, जो गंगा–यमुनी संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आज यह समृद्ध गंगा–यमुनी संस्कृति मौजूदा एकरंगी सत्ता की संकीर्ण सोच के कारण खतरे में है।

वाराणसी की शैक्षणिक, सांस्कृतिक महत्ता के कारण ही सर्व सेवा संघ के प्रकाशन विभाग का मुख्यालय वहां गंगा–वरुणा के पवित्र संगम पर स्थापित किया गया था। इसके लिए 1960, 1961 और 1970 में रेलवे से जमीन खरीदी गई थी। डिविजनल इंजीनियर उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित तीन सेल डीड संस्था के पास मौजूद हैं। जमीन के बदले रेलवे को चुकाई गई वाजिब धन राशि का प्रमाण भी मौजूद है। लेकिन आज का रेल विभाग इन सभी दस्तावेजों को कूटरचित बता रहा है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन रेल मंत्री बाबू जगजीवन राम ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्वीकृति से सर्व सेवा संघ को रेलवे की जमीन बेचने की अनुमति दी थी। तत्कालीन उद्योग मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो स्वयं संस्था से आजीवन जुड़े रहे, ने इस काम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यही नहीं, रेलवे ने गांधी विचार के प्रचार–प्रसार के लिए देशभर में रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टॉल के लिए जगह भी सर्व सेवा संघ को आवंटित किये थे। कई स्टेशनों पर आज भी ये बुक स्टॉल मौजूद हैं। आज वही रेलवे सर्व सेवा संघ के जमीनी दस्तावेजों को कूटरचित बता कर न सिर्फ इस संस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है, बल्कि विनोबा भावे, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण जैसी देश की विभूतियों को भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में यह कृत्य मौजूदा सरकार की एकांगी घृणास्पद सोच से उपजे अहंकार का परिणाम है। मौजूदा सरकार सिर्फ अपने अहंकार के पोषण के लिए सब कुछ मिटा देना चाहती है।

वाराणसी इसलिए भी मौजूदा सरकार के निशाने पर है कि वह इसके मुखिया का फिलहाल निर्वाचन क्षेत्र है। मुखिया उसे अपनी बपौती समझ बैठा है। वह नहीं चाहता कि उसके अपने क्षेत्र में दूसरे विचार वाली संस्थाएं मौजूद रहें, कार्य करें। इसके लिए तरह–तरह की ऊल–जलूल परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। परियोजनाओं के लिए जमीन के बहाने बारी–बारी से वाराणसी की विविध रंगी विरासतों पर जबरन बुलडोजर चलाए जा रहे हैं।

कोई भी सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तब वह लिर्लज्ज और क्रूर भी हो जाती है। सर्व सेवा संघ भवन को जिस तरह खाली कराया गया, उस पर जबरन कब्जा किया गया, सरकार का क्रूरतम चेहरा सामने देखने को मिला। सर्व सेवा संघ परिसर में वहां काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं के परिवार भी रहते हैं। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ 22 जुलाई, 2023 को तड़के परिसर पर धावा बोल दिया। प्रशासन ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दीं। छोटे बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे तो कुछ अभी नींद में थे। पुलिस ने जबरन घरों में घुस कर सब को बाहर निकाल दिया। घरों के सामान निकाल

जब देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर निचली अदालत में मामला सुनवाई के लिए लम्बित हो तो ऐसे में सुनवाई से पहले ही सर्व सेवा संघ परिसर को जबरन खाली करवाना उचित नहीं। विरासतों को संजोने के बजाय उजाड़ देना क्षोभ उत्पन्न करता है।

सुविधाभोग और आधुनिकता के नाम पर काशी के पुरातन स्वरूप को विकृत किया जा रहा है। काशीवासी जागृत हों।

– शङ्कराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्दः सरस्वती

फेंके। परिसर के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए। न बाहर से अंदर किसी को आने की अनुमति न अंदर से बाहर जाने की अनुमति। परिसर की बिजली काट दी गई, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। छोटे–छोटे बच्चों तक को भूखे–प्यासे रहने को मजबूर किया गया। सर्व सेवा संघ की करोड़ों रुपये मूल्य की पुस्तकें खुले आसमान के नीचे कूड़े की तरह फेंक दी गईं। इन सब कृत्यों के पीछे शासन–प्रशासन के पास कोई वैधानिक तर्क नहीं था, सिवाय अहंकार के। रेलवे के साथ ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में मुकदमा लंबित है। अन्तिम फैसला आने से पहले इस तरह का कृत्य कोई सरकार नहीं, बल्कि सरफिरा ही कर सकता है। संविधान और कानून से चलने वाले किसी देश में यह कत्तई स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने सबसे पहले सर्व सेवा संघ परिसर में ही 1960 में जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित गांधी विद्या संस्थान पर कब्जा किया और उसे सरकारी संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया। और अब पूरे परिसर पर उसने कब्जा कर लिया है। हम सरकार को बड़ी विनम्रता के साथ याद दिलाना चाहते हैं कि कभी इसी तरह का कब्जा पूरे देश पर अंग्रेजों ने कर लिया था। तब एक बूढ़ा अधनंगा फकीर अंग्रेजों के सामने खड़ा हो गया था। बापू ने देश भर में घूम–घूम कर आम जनता को भी खड़ा किया। उन्होंने अहिंसक संघर्ष के जरिए अंग्रेजी शासन से मुक्ति का मार्ग दिखाया और हम मुक्त हो गए। वह मार्ग हम गांधीमार्गियों के पास आज भी है। हम कुमार्गी हो चुकी सत्ता को मार्ग पर आने के लिए मजबूर करेंगे। हमारा अहिंसक संघर्ष शुरू हो चुका है। गांधी–विचार में आस्था रखने वाले देश के नागरिक एकजुट हो रहे हैं। अहंकारी सत्ता अपने आप तास के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। जीत अंततः सत्य की होगी।

क्या आप जानते हैं ?

1. काशी में प्रस्तावित इंटर मॉडल स्टेशन गंगा के डूब क्षेत्र में बन रहा है जो भविष्य में वाराणसी को दिल्ली की तरह डुबो सकता है। हाई कोर्ट ने इस क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा है।

2. प्रोजेक्ट में प्रस्तावित पांच सितारा होटल आदि पुरातात्विक महत्व के स्थान के करीब में बनेगा जो गैर कानूनी है।

3. यहीं पर गंगा सफ़ाई के लिए कछुआ सैंक्चुरी है और यह प्रोजेक्ट वाइल्डलाइफ़ कानून का उल्लंघन करता है।

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सर्व सेवा संघ की कुछ ज़मीन का अधिग्रहण करना है। इसका मतलब सर्व सेवा संघ इस ज़मीन का कानूनी मालिक है।

सोचिए हम मां गंगा, महात्मा गांधी की विरासत और बनारस को बड़ी कंपनियों की गिद्ध दृष्टि से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।

हम इनके विरोधी इसलिए भी हैं क्योंकि हम प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, नग्न पूंजीवाद के खिलाफ़ हैं और सर्वोदय साहित्य, प्रकृति के संरक्षण और इस सरकार की प्रकृति विरोधी नीतियों को बेनक़ाब करते आये हैं, इसलिए इन्होंने पूरे सर्व सेवा संघ को ही नेस्तानाबूद करने की सोच लिया है। लेकिन अब आप सब, देश के नागरिकों को सोचना है कि आप उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। बनारस के लोगों को बनारस के हर गली, मोहल्लों और गावों में रहने वाली जनता को इस बात को समझाना होगा और बनारस के वास्तविक स्वरूप को, पवित्रता को बचाना होगा !

मतांध सरकार और गांधी के लोग

डॉ. सुजाता चौधरी

ब्रिटेन के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री चर्चिल ने महात्मा गांधी को लंगोटी और रबड़ की चप्पल में रायसिना हिल पर निर्मित वायसराय के महल की सीढ़ियों पर चलते देखा तो रोष में भरकर कहा था -- मेरी इच्छा होती है इस अधनंगे फकीर को रौंदवा दूं।

चर्चिल की तमन्ना पूरी नहीं हुई लेकिन आज मतांध सत्ता गांधी विचार की महत्वपूर्ण संस्था "सर्व सेवा संघ" को रौंदने के लिए बुलडोजर लेकर खड़ी है। एक ओर सत्ता के मद में बौराई सरकार है तो दूसरी ओर सत्याग्रही लोगों का समूह, जिनके पास गांधी, जयप्रकाश, विनोबा के विचार के अलावा कोई पूंजी नहीं है।

परंतु हमारे देश की सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था भारत की जागरूक जनता ने ही उस साम्राज्य का अस्त करा दिया था।

सर्व सेवा संघ, वाराणसी पर सत्ता के बुलडोजर चलाने की कवायद देश के सबसे आदर्श और ईमानदार रेलमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ईमान पर प्रहार है। संत विनोबा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर हमला है, जिन्होंने कभी सत्ता के आगे शीश नहीं झुकाया।

हमारी सरकार सर्व सेवा संघ के भवन को ध्वस्त कर देना चाहती है और उसके जमीन को रेलवे की जमीन होने का दावा कर उसे रेलवे की संपत्ति में शामिल करने का षड्यंत्र कर रही है। यह एक संस्था पर प्रहार है या भूमि हड़पने की साजिश है ?

क्या उपरोक्त दोनों बातों से अलग, कुछ अंदरूनी बातें हैं ? क्या यह महात्मा गांधी के विचारों को ध्वस्त करने की एक जबरदस्त मुहिम का एक हिस्सा है ?

यह जमीन लाल बहादुर शास्त्री ने जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे की साक्षी में सर्व सेवा संघ को दिया था, जिसकी रजिस्ट्री भी कराई गई थी। इन तीनों नामों की ईमानदारी पर ऊंगली उठाने वाले शायद सत्ता पक्ष में भी नहीं होंगे। फिर यह अन्याय क्यों हो रहा है ?

यह जमीन जब सर्व सेवा संघ को मिली, तब उसकी हालत अत्यन्त दयनीय थी। उस जमीन पर कहीं दलदल था तो कहीं बहुत बड़े--बड़े गड्ढे। हज़ारों की संख्या में उस समय के नैतिकता से ओतप्रोत गांधीवादियों ने अत्यधिक शारीरिक श्रम करके जमीन को समतल बनाया। स्वयं कुदाल उठाया, सिर पर टोकरी उठाई, तब जाकर उस भवन का निर्माण हुआ, जहां बुलडोजर चलाने के लिए सरकार ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। जहां विनोबा जयप्रकाश और न जाने कितने स्वनामधन्य विभूतियों ने अपनी जिंदगी लगाई है। आज उसी सर्व सेवा संघ को जमींदोज कर सरकार क्या सबित करना चाहती है ?

हमारी सरकार का यह कुकृत्य सरासर अन्यायपूर्ण और विनाशक है। सर्व सेवा संघ को ध्वस्त करने की उसकी सोच सिर्फ एक गलती नहीं वरन अपराध और पाप है।

जिस गांधी के चरणों में विदेश जाने पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को भी नतमस्तक होना पड़ता है उसी गांधी के विचारों की संस्थाओं को नाश करने की कोशिश कितनी बड़ी त्रासदी साबित होगी, उसे आज हमारा देश शायद पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है।

जिस दिन गांधी के विचार ध्वस्त कर दिए जायेंगे, उस दिन भारत, यह भारत नहीं रहेगा, नफरतों का साकार मूर्तरूप बन जायेगा।

सर्व सेवा संघ को ध्वस्त करने का यह आदेश हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की गरिमा को भी तार--तार करता है और उनकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाता है।

सर्व सेवा संघ ने जो समाज और देश की अभी तक सेवा की है उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। आगे भी इस संस्था से बहुत सारी आशाएं हैं।

सर्व सेवा संघ ने गांधी और सत् साहित्य को बहुत कम मूल्यों में जन--जन तक पहुंचाया है। अंतिम जन तक पुस्तक पहुंचाने में वह सफल रहा है। ⇨

खादी के संदर्भ में एक सुझाव

तारा गांधी भट्टाचार्य

मेरा एक सुझाव है कि सब गांधी संस्थाओं में एक छोटा खादी उत्पादन केन्द्र बनाया जाना चाहिए। इस खादी केन्द्र में खांटी खादी बननी चाहिए।

आजकल मैं खादी कमीशन की दुकानों के साथ निजी दुकानों में भी देख रही हूं कि एक बड़े पैमाने पर खादी के नाम पर सिंथेटिक कपड़ा बहुत ही सहजता के साथ बेचा और खरीदा जा रहा है।

विश्व के संतों, सूफी कवियों, कलाकारों और चिंतकों को खादी के इस चरखे और करघे ने अध्यात्मिक प्रेरणा दी है। ठोस जमीन की यथार्थ और व्यवहारिकता में खादी का यह चरखा देश के लाखों लोगों की थाली में रोटी के रूप में आता है। खादी में एक विचार है, दार्शनिकता है। हाथ से कता और बुना कपड़ा मनुष्य संस्कृति की अनमोल विरासत है। खादी का यह कपड़ा न सिर्फ भारत देश का है, न सिर्फ गांधी का है बल्कि यह सम्पूर्ण विश्व की मानवीय संस्कृति का बुनयादी परिचय है।

यह सच है कि आज खादी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, किन्तु, एक विरोधाभास में, यह भी सच है कि खादी की समझ बहुत कम होती जा रही है।

महात्मा गांधी द्वारा पुनर्जागृत, विश्व के मनुष्य समाज की विरासत की रक्षा के लिए, गांधी संस्थाओं में एक छोटा खादी उत्पादक केन्द्र होना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। इस केन्द्र में छोटे–मोटे शुद्ध खादी के चादर और तौलिये बनाये जा सकते हैं। वह शुद्ध खादी होगी, शुद्ध खद्दर होगा। खद्दर के वस्त्र और विचार दोनों का दर्शन होगा।

इस विषय में मेरा मानना है कि यदि गांधी संस्थाओं में एक छोटा खादी उत्पादन केन्द्र का निर्माण होता है तो यह विश्व मानव समाज की संस्कृति के लिए, खद्दर के वस्त्र और विचार के प्रति हमारी बहुत महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि होगी।

➪ सत् साहित्य का समाज निर्माण में क्या योगदान है। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। नैतिकता के निर्माण से लेकर ज्ञान और संस्कृति को पल्लवित और पुष्पित करने का काम सर्व सेवा संघ प्रकाशन ने किया है।

हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जो यह कह पाते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, तो उसकी मजबूती में सर्व सेवा संघ जैसी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

सर्व सेवा संघ को ध्वस्त करने का मतलब है लोकतंत्र की इमारत की नींव से एक ईंट को निकाल देना। इस तरह की ईटों के निकलने से हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा और एक दिन ध्वस्त हो जाएगा।

अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसी संस्थाओं को बचाना होगा। सिर्फ सरकार ही लोकतंत्र की सर्वेसर्वा नहीं है, जनता भी है और जनता की संस्थाएं भी।

खासकर वैसी संस्थाएं जो भारतीय संस्कृति, मानवीयता, सत्य , अहिंसा, अधिकार और कर्त्तव्य जैसे मुद्दों पर देश को जागरूक बनाती हैं।

जीवंत संस्थाएं विपरीत परिस्थितियों के आने पर अक्सर नई ऊर्जा से संचारित होकर संघर्ष के लिए खड़ी हो जाती हैं। आशा है सर्व सेवा संघ भी इस घटना के बाद अपनी दीर्घ सूत्रता छोड़कर गांधी के एकादशी व्रतों से लैस होकर एक नए अवतार में खड़ी होगा।

सर्व सेवा संघ नए भारत के निर्माण में देश के सभी वर्गों को महिलाओं, युवाओं को शामिल करके गांधी के सपनों का भारत बनाने में योगदान करेगा।

राजदंड से सजाया गया लोकतंत्र

कुमार प्रशान्त

सब कुछ नया हो गया। संसद भवन भी नया हो गया, लोकतंत्र भी नया हो गया, समय के ललाट पर अमिट हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री ने संकल्प भी नया लिख दिया। यह भी एकदम नया हुआ कि संसद भवन का उद्घाटन समारोह हुआ, लेकिन न राष्ट्रपति थीं, न उप–राष्ट्रपति थे।

दोनों दिल्ली में ही थे, लेकिन उनके संदेश भर पढ़े गए, उन्हें मौजूद रहने से मनाही कर दी गई। 20 से ज्यादा विपक्षी दल नहीं थे, यह बात आपके लोकतंत्र में कोई मानी नहीं रखती। संविधान में यह बात ही गलत दर्ज हो गई है कि संसद में पक्ष और विपक्ष का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि वही लोकतंत्र है जिसमें दोनों की साझेदारी हो।

लोकतंत्र का अध्यक्ष उसका प्रथम पुरुष होता है, ऐसी कोई नई मान्यता बनाई जा रही है, तो वैसा भी कुछ बना नहीं; अध्यक्ष थे जरूर, लेकिन थे वे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व विहीन पिछलग्गू। इसकी पूरी सावधान योजना बनाई गई थी कि एक ही आदमी सुनाई दे, एक ही आदमी दिखाई दे, एक ही आदमी सरकार हो। लोकतंत्र एक ही आदमी का होता है, यह भी नया हुआ।

इतना नया–नया एक साथ इस तरह हुआ कि पुराना कुछ याद ही नहीं रहा। जैसे किसे याद रहा कि कहीं, इतिहास के किसी गतालखाने से कोई 'सेंगोल' लाया गया और हमने प्रधानमंत्री को उसके सामने साष्टांग भू–लुंठित देखा, मानो वह लोकतंत्र की कोई आदिशक्ति का साकार स्वरूप हो जिसकी साष्टांग अभ्यर्थना करना धार्मिक दायित्व हो।

क्या आपको याद है कि ऐसा पहली बार नहीं देखा हमने ? अगर मैं भूलता नहीं हूं तो हमने संसद के प्रवेश–द्वार पर प्रधानमंत्री को साष्टांग भू–लुंठित देखा है। हमने संविधान की किताब के सामने उन्हें नतमस्तक देखा है। हमने उन्हें मठों–मंदिरों–पंडों–पुजारियों के सामने नतमस्तक देखा है।

हमने उन्हें दलितों के पांव धोते देखा है। हमने उन्हें सार्वजनिक सभाओं में मंचों के हर कोने पर जा–जाकर जनता–जनार्दन को इस तरह नतमस्तक प्रणाम करते देखा है कि वह उपहास का प्रसंग बन गया। यह सब पुराने कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री जब भी, जहां कहीं होते हैं कुछ–न–कुछ नया होता ही है जो बेहद पुराना होता है। वैसे यह ठीक भी है कि वे देश को नया बना रहे हैं तो उनका अपना नया बने रहना भी तो जरूरी है न। बस, ध्यान इतना ही रखना है कि यह सारा नया कोई दूसरा नहीं प्रधानमंत्री ही करें।

हमारे लोकतंत्र में 'सेंगोल' का प्रवेश एकदम नया है। प्रधानमंत्री ने उसे खोजा, धूल झाड़ी, उसे चमकाया, हथेलियों में उठाया, फूलों से सजाया, उसके सामने साष्टांग दंडवत हुए, फिर उसे लेकर पैदल चले, अध्यक्ष के आसान के पास एक खास जगह गढ़ी उन्होंने, उसका एक खास स्टैंड बनाया जिस पर उसे पूजा–पाठ के साथ स्थापित किया। फिर देश को यह भी सिखलाया कि यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यह राजदंड है।

अध्यक्ष के आसन के पास है तो इसलिए कि सदस्य (वे सदस्य जो विपक्ष के होते हैं।) सदन की मर्यादा का पालन नहीं करते तो अध्यक्ष उसे तत्काल 'सेंगोल' से बरज सकें। नहीं, नहीं, हमने गलत लिखा। अध्यक्ष नहीं, बरजेंगे तो प्रधानमंत्री ही, अध्यक्ष उनसे निवदन करेंगे कि 'सेंगोल' का वक्त आ गया है श्रीमान, आइए और इन महाशय को दंडित कीजिए। राजदंड दंडित करने के लिए ही होता है।

बेकार ही बहुत सारा इतिहास खंगाला गृहमंत्री शाह ने। यह 'सेंगोल' कहां से आया, किसने इसे कब किसे दिया, आपका यह सारा शोध कबूल है। शाह साहब, लेकिन समझने की बात तो इतनी ही है कि लोकतंत्र से इस 'सेंगोल' का कोई नाता बनता है क्या ? नहीं, इसका नाता राजतंत्र से है। देखिए, आपने 'सेंगोल' की बात की तो न चाहते हुए भी आपको जवाहरलाल नेहरू को उस इतिहास में जगह देनी पड़ी जिस इतिहास को बदलने–भुलाने में आप और इतिहास के आपके इतने सारे दिग्गज लगे हुए हैं।

जवाहरलाल नेहरू को समझना उन सबको भारी पड़ता है जिनको लोकतंत्र का ककहरा न भाता है, न समझ में आता है, लेकिन नेहरू को जब यह 'सेंगोल' मिला तो उन्होंने इसे➪

अलविदा मिलान कुंडेरा

कुमार प्रशान्त

मिलान कुंडेरा नहीं रहे। मैंने तुरंत देखा कि वे कहां थे जब उनकी मृत्यु हुई ? इसलिए नहीं कि मुझे यह पता नहीं था कि वे पिछले कई वर्षों से फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहे थे बल्कि इसलिए कि वे जहां रह रहे होते थे, वहां होते नहीं थे। मुझे इसी मिलान कुंडेरा का अपार आकर्षण रहा है। वह साहित्यकार भी क्या साहित्य रचेगा जो धरती पर कहीं भी अपना संसार नहीं रच सके।

आप सोच कर देखिए कि मैं एक ऐसे लेखक की बात कर रहा हूं जिसे मैं जानता तो नहीं ही हूं, उसकी भाषा भी नहीं जानता। उसका देश भी मैंने कभी देखा नहीं। यह कहना भी जरूरी है कि उनकी हर रचना मैंने पढ़ी हो, ऐसा भी नहीं है। उनका अधिकांश साहित्य चेक भाषा में है; जब चेक में लिखना उन्होंने घोषणापूर्वक छोड़ दिया, तब के बाद से उनके साहित्य की भाषा फ्रेंच हो गई। मुझे इन दोनों में से एक भाषा भी नहीं आती है। हममें से अधिकांश लोग मिलान कुंडेरा को अंग्रेजी माध्यम से जानते हैं – अंग्रेजी, जिस भाषा में उन्होंने कभी लिखा नहीं तो फिर आप ही बताइए, ऐसे लेखक को मुझ जैसा कोई जानेगा भी तो कैसे व कितना! लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं मिलान कुंडेरा को लगातार अपने आसपास पाता रहा हूं – एक दोस्त लेखक की तरह नहीं, एक सहयात्री की तरह !

यह भी कहना जरूरी है कि यदि निर्मल वर्मा न होते तो मेरे पास मिलान कुंडेरा भी नहीं होते। निर्मल वर्मा ने ही मिलान कुंडेरा से, उनके लेखन से मेरा परिचय करवाया था। वह दुबचैक का चेकोस्लोवाकिया था जिसे रूसी टैंकों ने घेर कर मार डाला था – बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह आज वे ही रूसी टैंक यूक्रेन को घेर कर मारते जा रहे हैं। तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है कि सारी दुनिया तमाशबीन बनी हुई है। निर्मल वर्मा तब चेकोस्लोवाकिया में थे और चुप नहीं थे; यहां भारत में जयप्रकाश नारायण थे और चुप नहीं थे।

जब भारत में कोई सोवियत खेमे के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं करता था, जयप्रकाश चेक लोगों की स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर सामने आए थे, एक दबाव खड़ा करने की कोशिश भी की थी। मानवीय गरिमा के हनन पर जो साहित्य चुप रहे तो वह साहित्य नहीं है; जो गांधीवाला चुप रहे, वह गांधीवाला नहीं है; मेरी यह समझ उसी दौर में बनी। उसी दौर में मिलान कुंडेरा का साहित्य भी बना। विचार न हो तो आदमी होना शक्य नहीं है; प्रतिबद्धता न हो तो कलम उठाने से अर्थहीन काम दूसरा नहीं है। प्रतिबद्धता और ढोलबाजी में जो फर्क है, उसका विवेक खोये नहीं, यह जरूरी है। मुझे कुंडेरा इसलिए ही पसंद

➪इसकी सही जगह पहुंचा दिया। किसी संग्रहालय में रखवा दिया। राजदंड लोकतंत्र का प्रतीक नहीं बन सकता इतना विवेक था उन्हें। लोकतंत्र का एक मतलब, जरूरी मतलब यह भी है कि आपको अपनी समझ, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, अपनी पोथियां, अपनी मान्यताएं सब शनै–शनै बदलनी पड़ती हैं।

कपड़ा बदलने के बारे में तो कबीर साहब कब के कह गए हैं कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, लेकिन यहां तो लोकतंत्र कपड़े से आगे, मन व मान्यताओं के बदलाव की मांग करता है। लोकतंत्र से जिसका मेल नहीं बैठता, वह सारा कुछ किसी संग्रहालय में जगह पाता है। लोकतंत्र के आंगन में तो वही प्रतिष्ठित होता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को संवारता–पुष्पित–पल्लवित करता है।

इसलिए 'सेंगोल' की जगह संसद में नहीं है। जैसे ईंट–सीमेंट की बनी इमारत लोकतंत्र की संसद नहीं होती, वैसे ही राजतंत्र के किसी प्रतीक की जगह भी संसद में नहीं होती। संसद में आप करते क्या हैं, कैसे करते हैं और जो करते हैं वह संविधानसम्मत है या नहीं, यही कसौटी है कि वह लोकतंत्र की संसद है या नहीं। हमारी संसद में लोकतंत्र की जगह पहले ही कम थी, आपने उसे और भी संकरे रास्ते पर ला खड़ा किया है, लेकिन आप भी क्या करें, आपके लोकतंत्र में जगह ही एक आदमी की है, इसलिए आपकी परिकल्पना भी उतनी ही संकरी है।

थे, अपने–से–लगते थे। वे बला की प्रतिबद्धता से लिखते रहे लेकिन उनके समस्त लेखन में कोई ढोलबाजी नहीं थी।

वे साम्यवादी देश चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए थे। तब का साम्यवाद वह नहीं था जो आज का है – पूंजीवादी घोड़े की दुम पकड़ कर, साम्यवादी नारेबाजी करने वाला विदूषक! वह दुबचैक का दौर था जब वे अपने चेकोस्लोवाकिया में, रूस की तनी भृकुटि के बावजूद साम्यवाद का 'मानवीय चेहरा' बनाने में लगे थे। युवा कुंडेरा उन दुबचैक के साथ खड़े हुए। इसके बाद का पूरा इतिहास रूसी साम्यवादी शासन के पतन का इतिहास है जिसमें कितनी ही मूर्तियां टूटीं, कितनी आस्थाएं बिखरीं तथा कितने ही लोग मिटा दिए गए। दुबचैक खुद ही किसी गतालखाने में डाल दिए गए। कुंडेरा ने स्वप्नों के बिखरने के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। फिर वही हुआ जो सबसे सहज था : जिस साम्यवादी पार्टी के वे सदस्य ही नहीं थे बल्कि जिसकी पैरवी करने में वे कुछ भी उठा नहीं रखते थे, उसी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। जितनी आजादी हम दें, उसमें खुश रहकर दिखाने वाले साम्यवाद के साथ कुंदेरा का बनना नहीं था; नहीं बना।

पार्टी छोड़ी फिर देश छोड़ा। रूसी सोल्जेनित्सीन को भी सोवियत संघ छोड़ना पड़ा था और वे जा बसे थे अमरीका में। उनसे देश तो छूटा लेकिन वे कभी देश छोड़ नहीं सके। कुंडेरा ने अपना प्यारा देश छोड़ा, तो ऐसे छोड़ा कि छोड़ ही दिया। पेरिस में आ बसे तो वहीं के होकर रह गए। भाषा भी छोड़ दी। फ्रेंच में लिखने लगे। लेखक किसी देश का नहीं, मूल्यों का होता है। अगर मूल्यों की पहचान साफ है और उनके प्रति प्रतिबद्धता पूरी है तो कहीं भी रहो, लिखोगे वही जो लिखना है; और जो लिखना जरूरी है। कुंडेरा ऐसी मान्यता को जीते थे। इसलिए फ्रांस में रहते हुए उन्होंने आजादी, अभिव्यक्ति और अस्मिता तीनों पर लगातार काम किया।

आप कुंडेरा को बोलते कम ही सुनते थे क्योंकि वे मानते थे कि लेखक को नहीं, उसकी रचना को बोलना चाहिए। 1968 में उनकी पहली किताब आई 'जोक्स' यानी हंसी–मजाक! लेकिन सत्ता समझ गई कि यह हंसी–मजाक नहीं है, तेजाब है। हंसी–मजाक का आलम यह है मिलान कुंडेरा के यहां कि किताबों के नाम भी उसी की बात करते हैं – लाफेबल लव्स, द बुक ऑफ लाफ्टर; लेकिन आप हंसी–मजाक में इसे उठा लेंगे तो फंस जाएंगे। उनकी आखिरी किताब आई 'द अनबेयरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग' – अस्तित्व ऐसा कि हवा में तिरता पंख हो; प्रतिबद्धता ऐसी ही कि जैसे पहाड़ उठा रखा हो, इसका द्वंद्व है यह उपन्यास। साम्यवादी दर्शन व संचालन में दमन और हिंसा का अतिरेक ही कुंडेरा को परेशान नहीं करता है, वे उसकी व्यर्थता को पहचानते भी हैं और हमें दिखाते भी हैं। हैरान भी होते हैं कि ऐसी व्यर्थ हिंसा से हासिल क्या होता है। गांधीजी ने भी हिंसा की क्रूरता से अधिक, उसकी निरर्थकता को बार–बार उभारा है। कुंडेरा भी उसे पहचानते हैं। यह उपन्यास लिखने के बाद कुंडेरा ने लिखना करीब–करीब बंद ही कर दिया। फिर आई 'ए किडनैप्ड वेस्ट : द ट्रेजडी ऑफ सेंट्रल यूरोप'। इसके साथ कुंडेरा का जीवन भी समाप्त हुआ।

कुंडेरा बार–बार लिखते रहे कि हम कितनी बड़ी संभावनाओं तक पहुंच सकते थे लेकिन हम कितनी बुरी तरह चूकते रहे हैं। साम्यवाद को वे इसी नजरिये से विश्लेषित करते हैं। हम भारत में पहचान तो पाएंगे कि सांप्रदायिकता का जो तूफान आज खड़ा किया गया है और जो जहर इसकी नसों में उतारा जा रहा है, वह कितना अर्थहीन है। हम जैसे खुद अपना ही कार्टून बना रहे हैं। दूसरों के लिए हम जो कब्र खोद रहे हैं, उसमें दफन हम ही होंगे। यह आत्महत्या नहीं, आत्मविद्रूपण है जिसमें से ग्लानि के सिवा दूसरा कुछ हाथ नहीं आएगा। मानव मात्र को यही ग्लानि मिली है हर उस सत्ता व सत्ताधीश से जो हिंसा व घृणा को उकसाता है। कुंडेरा बार–बार यही समझाते हैं।

94 वर्ष की उम्र में अब वे थक कर सो गए हैं। उन्होंने खुद को कभी विस्थापित या शरणार्थी नहीं माना। हमेशा लेखक की भूमिका में रहे और कहते रहे कि हम कभी जान ही नहीं सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं; क्योंकि हमारे हाथ तो यही एक जिंदगी है जिसकी पहले वाली जिंदगी से तुलना करने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है; न भावी जिंदगी संवारने की कोई नई तस्वीर हमारे पास है।

हां, मिलान कुंडेरा, हम नई–पुरानी तो नहीं जानते लेकिन सपनों की वह तस्वीर हमारे पास है जो आपने उकेरी है। आपका आभार कि आप हमें उस दहलीज तक ले गए।

मंत्री की कलम से

दक्षिण क्षेत्रीय गांधीजन सम्मेलन : गांधी भवन, तिरुवनंतपुरम्, केरल

गांधी स्मारक निधि की राज्य इकाइयों का दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन गांधी भवन, तिरुवनंतपुरम्, केरल में 24–25 जून, 2023 को आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्‌घाटन गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री रामचन्द्र राही ने किया। स्वागत भाषण में केरल गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष डॉ. एन. राधाकृष्णन ने कहा केरल गांधी भवन में लंबे समय के पश्चात इस तरह का सम्मेलन हो रहा है। दक्षिण के तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल से उपस्थित गांधीजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अहिंसा के समाज–निर्माण तथा स्वावलंबी जीवन–शैली के विकास में केरल के गांधीजनों के कामों को जानने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस सम्मेलन में केरल के गांधीजनों और युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। देश में व्याप्त हिंसा का सामना अहिंसा से किया लिया। शांति का मार्ग ही गांधी का मार्ग है।

श्री रामचन्द्र राही ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि मुझे आज स्व. पी. गोपीनाथन्‌जी खूब याद आ रहे हैं, लंबे समय तक उनके मार्ग–दर्शन और प्रेरणा से काम करने का सौभाग्य मिला। दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में हमारी संस्थाओं की सक्रियता और यहां की उपस्थिति हमारे काम की व्यापकता को प्रदर्शित करती है। लगभग सौ वर्षों की साधना का फल है कि गांधी–विचार ने ही यहां के गांवों को समृद्ध किया। दक्षिण की उदारवादी सोच तथा यहां की बौद्धिक कसौटी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण के जरिये समाज की भलाई करने की तत्परता ने यहां के समाज को समृद्ध किया। गांधीजी ने बार–बार दक्षिण का भ्रमण किया।

आज भारत में सद्‌भावना, भाई–चारा की कमी तथा माहौल चिन्ताजनक है, मणिपुर में हिंसा से हम सब दुःखी हैं। ऐसे समय में अहिंसा और शांति के लिए कार्य करने वाली गांधी–विचार की संस्थाओं पर सरकार के आक्रमण से देश में गांधी–विचार और संविधान के मूल्यों को विपरीत दिशा में धकेलने का खतरा उत्पन्न हुआ है। श्री ए. अण्णामलाई ने गांधी स्मारक निधि के दक्षिण राज्यों के आपसी साझा सम्बन्ध स्थापित करने पर बल दिया। उन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर गांधी–विचार के प्रभाव पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किये। श्री संजय सिंह ने कहा कि पांचों राज्यों के हमारे कार्यकर्त्ता सीमित साधनों में भी जी–जान से काम कर रहे हैं, जो गांधी–विचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे ग्राम सेवा केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में सेवा में तत्पर जो गांधी केन्द्र हैं उन्हें और मजबूत करने की दिशा में यह सम्मेलन कार्यक्रम तैयार करे। इस सत्र में डॉ. जेकब पुलीकन ने संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इसके पश्चात कर्नाटक गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री उडई पी. कृष्णा ने विस्तारित कार्यक्रम तथा कर्नाटक की वर्तमान स्थिति को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनके काम से सभी लोग प्रेरित हुए। तेलंगाना के सचिव श्री रंगा राव ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस तरह लगभग 30 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने कार्यक्रम और चुनौतियों के बारे में अपने विचार एक–दूसरे से साझा किये।

सम्मेलन के दूसरे दिन गांधी स्मारक निधि के पूर्व अध्यक्ष स्व. पी. गोपीनाथन् नायर के निवास पर पहुंच कर उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती अम्मा ने सबका स्वागत किया। वहां एक छोटी–सी गोष्ठी हुई। आस–पास के गांधीजन भारी संख्या में उपस्थित रहे।

इसके पश्चात केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि के पूर्व सचिव तथा विख्यात गांधीवादी श्री जी. रामचन्द्रन की जन्म–स्थली नैयाटिंकरा में डॉ जी. रामचन्द्रन विद्यालय में कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्थानीय गांधीजन, विद्यार्थी शिक्षक–शिक्षिकाएं आदि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर केरल के कई गांधीवादियों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन में सर्वश्री सूर्यनायक, जी. वी. शिवराजू, प्रो. प्रसन्ना और विशू कुमार आदि अनेकों गांधीवादियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के समापन में दो प्रस्ताव पारित हुए – (1) मणिपुर में बड़े पैमाने में हो➪

प्रकाशन तिथि 28/07/2023
Delhi Postal Regd. No. DL (C)-05/1423/2022-2024
R.No.21841/1971 Posted at L.P.C.- Delhi. R.M.S.Delhi-6 on 1st, 2nd August, 2023

विश्वहित से अविरोधी और वृत्ति में सर्वभूतानकूल्य–सेवा

आचार्य विनोबा

समाज–सेवा, सार्वजनिक सेवा इत्यादि शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। दरअसल प्रत्यक्ष में सर्वजनों की सेवा करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। समाज की या सर्वजन की हम भक्ति कर सकते हैं। प्रत्यक्ष सेवा हम अपने मक्दूर के अनुसार कुछ व्यक्तियों की ही करते है। वह करते समय विश्वहित से अविरोध और वृत्ति में सर्वभूतानुकूल्य हो, तो हमारा कर्त्तव्य पूरा होता है। अन्यथा विश्वरूप के दर्शन के पीछे लगा हुआ मनुष्य परेशानी उठाने के अलावा और कुछ सेवा कर नहीं सकेगा।

कहा जाता है कि जो स्कूल सबके लिए होंगे, उनमें सांप्रदायिक धर्म की शिक्षा का विषय रखना संभव नहीं है और इसलिए वह न रखा जाये। परन्तु मैं कहता हूं कि मैं सबके लिए नहीं, मेरे अपने परिवार के बच्चों के लिए ही एक छोटा–सा वर्ग चलाता हूं तो वहां भी सांप्रदायिक धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए।

परंतु ईश्वर के नाम को, फिर चाहे वह राम हो, रहीम हो या और कुछ हो, मैं सांप्रदायिक नहीं मानता। स्थितिप्रज्ञ–लक्षण, भगवद्गीता, सरमन आन दि माऊंट (गिरि–प्रवचन) या ऐसा सत्यनिष्ठा बढ़ानेवाला साहित्य, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पोशाक में हो, मेरी व्याख्या के अनुसार सांप्रदायिक नहीं है।

भिन्न–भिन्न जगहों के लोगों का धर्म उनकी भिन्न–भिन्न भाषाओं में मिल सकता है। संतों का साहित्य बहुत–सारा संप्रदायवर्जित, शुद्ध, निर्दोष ईश्वरनिष्ठा सिखानेवाला है। उसके चयन पर, जिस भाषा में वह होगा, वह भाषा बोलनेवाले सभी का अधिकार है। उसका अध्ययन करना सभीको लाभदायी होगा। जैसे, हम मराठी भाषाधर्मी लोगों को ज्ञानदेव से गीताई तक के संप्रदायर्जित परिशुद्ध भक्तिमार्ग का आधार निःशंकता से लेना चाहिए।

मिश्र–मंडलों में ही नहीं, विशिष्ट मंडल में भी सर्वधर्मों से चुना हुआ कुछ हिस्सा ले सकते हैं। वह यथासंभव प्रांतीय भाषा में हो। जैसे **आरंभीं देवाचें नांव** (बिस्मिल्लाहिर् रह्मानिर्रहिम) इत्यादि इस्लाम की प्रार्थना का मराठी अनुवाद। या तत्सम कोई अन्य चयन जरूर होना चाहिए। चयन में परिमाण का महत्त्व नहीं है। हिंदू कुटुंब में ऐसा कोई एक अन्यधर्मीय, लेकिन असांप्रदायिक अर्थ का सुवचन हो, तो बस है। मुसलमान परिवार में ऐसा ही कोई एक हिंदू, ईसाई सुवचन पर्याप्त होगा।

इससे भी आगे जाकर में कहूंगा कि विश्वप्रेम की वृत्ति रखकर असंकुचित बुद्धि से, भक्तिपूर्वक कोई भी वचन, फिर वे चाहे जिस मानवीय ग्रंथ के हों या सामान्य पुस्तक के हों, स्वीकारने में कोई हरज नहीं है।

(विनोबा साहित्य : खण्ड–13, पृष्ठ 185–186)

➪रही हिंसा तथा अशान्ति समाप्त करने के लिए तथा (2) सर्व सेवा संघ के वाराणसी केन्द्र में सरकारी अतिक्रमण और दमन के विरुद्ध।

कार्यक्रम आयोजन में डॉ. जेकब, केरल गांधी स्मारक निधि के मंत्री गोपालकृष्णन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केरल गांधी स्मारक निधि और केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि के मंत्रियों ने आभार व्यक्त किया।

– संजय सिंह

स्वामी गांधी स्मारक निधि के लिए राजघाट, नई दिल्ली–110002 से संजय सिंह, गांधी स्मारक निधि द्वारा प्रकाशित व मुद्रित
जैन ऑफसेट प्रिंटर्स, 198/2–1, फारचुन टावर, रमेश मार्केट, नई दिल्ली–110065
सम्पादक – रामचन्द्र राही